



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8 ]  
No. 8 ]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2000/पौष 27, 1921  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2000/PAUSA 27, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2000

विषय :—रूस तथा यूरोपीय संघ (ई.यू.) से विटामिन सी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

प्रारंभिक जांच-निष्कर्ष

सं. 26/1/99-डीजीएडी.—सीमाशुल्क टैरिफ आधोनेयम, 1975 (1975 मै यथा संघोधित) तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. कार्यपद्धति

1. जांच के लिए निम्नलिखित कार्य पद्धति अपनाई गई है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) को उपरोक्त नियमावली के अधीन मैसर्स अम्बालाल साराभाई एंटर प्राइसिस से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें रूस तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें इसके बाद सम्बद्ध देश कहा जाएगा) मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-सी के पाटन का आरोप लगाया गया है।
- (ii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रमाण के आधार पर सम्बद्ध देशों से विटामिन-सी के आयातों के विरुद्ध जांच प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इन नियमों के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले प्राधिकारी ने पाटन का आरोप प्राप्त होने के बारे में सम्बद्ध देशों के दूतावासों/शिष्टमंडल को सूचित किया।

(iii) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 2936-2700 के अन्तर्गत वर्गीकृत, सम्बद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन-'सी' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरंभ करते हुए तारीख 10 अगस्त, 1999 की एक सार्वजनिक सूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित कराई।

(iv) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातिकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग संघों को भेजी, और उन्हें नियम 6 (2) के अनुसार अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया।

(v) प्राधिकारी ने भारत में विटामिन-'सी' के ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उनसे इस पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार लिखित रूप से देने के लिए कहा।

(vi) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से जांच अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में विटामिन-सी के आयातों का विवरण देने का अनुरोध किया गया था।

(vii) प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातिकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को भेजी।

(viii) प्राधिकारी ने सम्बद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए नियम 6(4) के अनुसार रूस तथा यूरोपीय संघ के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातिकों को प्रश्नावली भेजी:-

**रूस**

- मैसर्स बैलविटामिनी, आईएनसी, बैलगौरोड
- मैसर्स इम्यूनो प्रेपरेशन्स प्लांट
- मैसर्स ज्वांइट स्टाक कम्पनी कारक्योफार्म
- मैसर्स शैलकोवसकी विटामिन प्लांट
- मैसर्स ज्वांइट स्टाक कम्पनी स्विटविटा
- एनपीओ विटामिन्स

**यूरोपीय संघ****यू.के.**

- मैसर्स हॉफमैन-ला-रोश, स्काटलैंड
- मैसर्स लापोरेट इंडस्ट्रीज लि., लंदन
- मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स लि; हीनर

जर्मनी

- मैसर्स बायर एजी
- कल्टर फूड साईंस गंभ
- बी.ए.एस.एफ. एक्टीएंग सैल शैफ्ट
- हैफमैन ला रोशे एजी
- मर्क के.जी.ए.ए.
- (ix) प्रश्नावली का उत्तर बी.ए.एस.एफ. एक्टीस सैलशैफ्ट, जर्मनी, मै. बॉयर एजी, मैसर्स मर्क के.जी.ए.ए., जर्मनी और मैसर्स कल्टर फूड साईंस गंभ से प्राप्त हुआ। अन्य किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।
- (x) सम्बद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों/शिष्टमंडलों को भी नियम 6(2) के अनुसार जांच आरंभ किए जाने की सूचना दे दी गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली भरकर भेजने की सलाह-दें। इस पत्र, याचिका और निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली की प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित दूतावासों को भी भेजी गई थी।
- (xi) नियम 6(4)के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए विटामिन-सी के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/होलसेल डीलरों को भी एक प्रश्नावली भेजी गई थी:-
- मैसर्स एंग्लो-फ्रेंच ड्रग्स कं. (ईस्टर्न) लि., बंगलौर।
- मैसर्स अमरीकन रेमीडीज, मद्रास।
- मैसर्स भारत लेबोरेटरीज सप्लायर्स, मुंबई
- मैसर्स क्रिस्टल फार्मास्यूटिकल्स
- मैसर्स कैमी फार्मा, मुंबई
- मैसर्स सी.जे. शाह एंड कम्पनी, मुंबई
- मैसर्स कान्सैप फार्मा लि., मुंबई
- मैसर्स दिलीप कुमार एंड कम्पनी, मुंबई
- मैसर्स इरोज फार्मा लि., बंगलौर
- मैसर्स फोर्ट्स (1) लैब्स, प्रा. लि. मद्रास
- मैसर्स ग्लैक्सी इंडिया लि., मुंबई
- मैसर्स ग्राक्यूर फार्मास्यूटिकल्स लि., नई दिल्ली
- मैसर्स खरीना फार्मा, दिल्ली
- मैसर्स के. सेवेंटीलाल एंड कम्पनी, मुंबई
- मैसर्स लैप्स कैमिकल्स प्राइवेटिड लि., मुंबई
- मैसर्स लालचंद मीमराज, मुंबई
- मैसर्स मैरिट आर्गनियन लि., मुंबई
- मैसर्स मरकरी लैब्स लि., मुंबई
- मैसर्स मैडले लैब्स, मुंबई

- मैसर्स मेदी फार्मा ड्रग हाउस, मुम्बई
- मैसर्स नेमी फार्मा प्रा. लि., वाकेश्वर
- मैसर्स पूजा एंटर प्राइसिज, मुम्बई
- मैसर्स प्रदीप कुमार एंड कम्पनी, मुम्बई
- मैसर्स फार्मास्यूटिकल्स इंडिया, मुम्बई
- मैसर्स रेकन लि., बंगलौर
- मैसर्स रेमीडेक्स फार्मा प्रा. लि., बंगलौर
- मैसर्स स्ट्राइड फर्मा लि., मुम्बई
- मैसर्स सनवेज प्रा. लि., मुम्बई
- मैसर्स तारू एंटरप्राइसिज लि., मुम्बई
- मैसर्स तुरखा ब्रदर्स, मुम्बई
- मैसर्स टी.एम. कुमार ठाकुर फर्मलैब्स, मुम्बई
- मैसर्स टेबलैट्स इंडिया लि., चेन्नई

तथापि विटामिन-सी के आयातकों ने निम्नलिखित उत्तर दिया:-

- मैसर्स के. सेवेंटीलाल एंड कं., मुम्बई
- मैसर्स मेदी फार्माड्रग हाऊस, मुम्बई
- (xii) क्षति के बारे में याचिकाकर्ता से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो उन्होंने दे दी थी।
- (xiii) प्राधिकारी ने, अपने पास सार्वजनिक फाइल के रूप में रखे गए, विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अश उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा देखने के लिए खुला रखा;
- (xiv) प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग की मौके पर जांच की;
- (xv) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) तथा याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में विषयगत माल की इष्टतम उत्पादन लागत तथा माल को बनाने और बेचने की न्यूनतम लागत का हिसाब लगाने के लिए लागत जांच भी की गई;
- (xvi) \* \* \* \* यह चिह्न इस अधिसूचना में एक हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा ही माने जाने का द्योतक है;
- (xvii) जांच 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक की अवधि के लिए की गई थी।

#### याचिकाकर्ता के विचार

3. याचिकाकर्ता ने विटामिन-सी के पाटन तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

### पाटन

(क) भारत में विटामिन -सी का पाटन रूस तथा यूरोपीय संघ के निर्यातकों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन देशों से आयात न केवल अधिक हो रहे हैं अपितु इनसे भारतीय बाजार में विटामिन-सी की बैंचमार्क कीमत भी निर्धारित होती है।

(ख) यूरोपीय संघ में विटामिन-सी का आयात युनाइटेड किंगडम तथा फैज़ेरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में विटामिन-सी का आयात इटली, फांस और डेनमार्क से भी किया जा रहा है। ये देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। यूरोपीय संघ में विटामिन-सी के अन्य कई उत्पादक हैं। यूरोपीय संघ में कोई सीमाशुल्क बंधन नहीं है। अतः पाटनरोधी शुल्क समस्त यूरोपीय संघ के विरुद्ध शुल्क लगाए बगैर कारगर नहीं हो सकता क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद अन्य उत्पादक भारतीय बाजार में विटामिन-सी का पाटन करना शुरू कर देंगे। यहां तक कि पाटन-रोधी शुल्क का निवारण जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम के उत्पादकों के लिए भी कठिन नहीं होगा। अतः याचिकाकर्ता ने यूरोपीय संघ के विरुद्ध सामूहिक रूप से जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

(ग) यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी में उत्पादकों ने भारतीय बाजार में अपनी कीमतें कम की हैं। रूस के उत्पादक पहले विटामिन-सी का निर्यात नहीं कर रहे थे। इन देशों के निर्यातकों ने हाल ही में भारतीय बाजारों में पाटित कीमतों पर विटामिन सी का निर्यात करना शुरू कर दिया है।

(घ) भारत में विटामिन-सी रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी से मुख्यतः सीधे ही भेजा जाता है। तथापि, यह हांगकांग तथा सिंगापुर के व्यापारियों के माध्यम से भी थोड़ी मात्रा में आ रहा है।

(ड.) सम्बद्ध देशों से आयातों के बाजार शेयर में वृद्धि हो रही है। घरेलू मांग में सम्बद्ध देशों का हिस्सा 1996-97 में केवल 5.29% ही था जो 1998-99 में बढ़कर 19.07% हो गया।

### क्षति के बारे में

याचिकाकर्ता को क्षति हुई है जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है:-

(क) विटामिन-सी एक ऐसी औषधि है जिसकी कीमत औषधि मूल्य (नियंत्रण आदेश) के तहत नियंत्रित होती है और नियंत्रण 1970 से ही लागू है।

(ख) संबद्ध देशों द्वारा किए गए पाटन का अन्तर निर्धारित सीमा से अधिक है। संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से हुए आयातों की मात्रा निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने आयातों के प्रभाव के संचयी आकलन का दावा किया है, क्योंकि संबद्ध देशों की निर्यात कीमत की भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई कीमत से सीधी प्रतिस्पर्द्ध है। याचिकाकर्ता ने सभी संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी रूप से आकलन करने का अनुरोध किया है।

(ग) याचिकाकर्ता का विटामिन सी का उत्पादन वर्ष 1996-97 के 468.961 मी.टन से घट कर वर्ष 1998-99 में 287.299 मी.टन रह गया है।

(घ) घरेलू उद्योग की उपयोग क्षमता वर्ष 1996-97 के 109.26 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1998-99 में 59.04 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि यदि इन देशों से होने वाले आयात की मात्रा की मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही, तो घरेलू उद्योग का चालू वर्ष में उत्पादन वर्ष 1998-99 में किए गए उत्पादन से काफी कम होगा। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के पास अपना उत्पादन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।

(ङ.) घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान बेची गई मात्रा 413.694 मी.टन थी जो वर्ष 1998-99 के दौरान घट कर 234.729 मी.टन रह गई। घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई औसत मासिक बिक्री की मात्रा, जो मार्च, 1997 में 34.47 मी.टन थी, वर्ष 1998-99 में घट कर 19.56 मी.टन रह गई।

(च) याचिकाकर्ता द्वारा विटामिन सी के लिए की गई औसत घरेलू वसूली वर्ष 1996-97 के दौरान \*\*\* रु० प्रति किग्रा. थी जो वर्ष 1998-99 के दौरान घट कर \*\*\* रु० प्रति किग्रा. रह गई, जो लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है।

(छ) याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बावजूद घरेलू उद्योग को विक्रय मूल्य कम करने के लिए बाध्य किया गया है।

(ज) मार्जिन पर जबरदस्त दबाव के कारण घरेलू उद्योग को यह निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि वह अपनी मानव-शक्ति को सहनीय सीमा तक कम कर दे।

(झ) याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि वर्ष 1995-96 तक वे लाभ कमा रहे थे। संबद्ध देशों से होने वाले विटामिन सी के पाटन के कारण उन्हें विटामिन सी को अपनी उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विटामिन सी के प्रति किग्रा. पर \*\*\*\* रु. का घाटा हो रहा है।

(ज) पाटन आयात के चलते अत्यंत मूल्य गिरावट की वजह से घरेलू उद्योग को डीपीसीओ द्वारा निर्धारित मूल्य से भी कम पर माल बेचना पड़ रहा है।

#### ग. निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

#### 4. निर्यातकों के विचार

(क) मै० काल्टर फूड साईस, जर्मनी तथा मै० बेयर एजी, जर्मनी न्यामक निर्यातकों ने यह सूचित किया है कि उन्होंने भारत को संबद्ध सामग्री का निर्यात नहीं किया है।

(ख) मै० बी ए एस एफ अवितंजसेलशाफ्ट, जर्मनी तथा मै० मर्क केजीएए, जर्मनी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रस्तुत की हैं। निर्यातकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष में उचित स्थान पर जांच की गई तथा उन पर विचार किया गया है।

## 5. आयातकों के विचार

(क) केवल भारतीय उच्चायुक्त के पत्र के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए पाटन के दावे से गलत निष्कर्ष निकलेगा क्योंकि भारतीय उच्चायुक्त, विदेशों में प्रचलित घरेलू कीमतों की उचित रूप से जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं।

(ख) घरेलू उद्योग विटामिन सी के विनिर्माण के लिए 2-केटो गुलोनिक एसिड नामक अंतर्वर्ती उत्पाद का आयात चीन जनवादी गणराज्य से कर रहा है। इसलिए यह वांछनीय होगा कि पूरे विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों के मूल की विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए की जा रही इस प्रकार की हास्यास्पद पाटनरोधी जांच को छोड़ दिया जाए। इसके बदले निर्दिष्ट प्राधिकारी को अंतर्वर्ती उत्पाद पर लगाने वाले शुल्क में 10 प्रतिशत तक की कटौती करने की सिफारिश करनी चाहिए, जो भारतीय उद्योग को टिके रहने के लिए एकाधिकार की स्थिति प्रदान करने तथा अनुचित संरक्षण देने के बजाए एक उपयुक्त तरीका होगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी यदि घरेलू उद्योग पर्याप्त रूप से उत्पादन नहीं करते हैं तो विनिर्माण उद्योग का काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।

## घ. उठाए गए मुद्दों की जांच

6. निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई है और नियमों के बारे में उठाए गए मुद्दों तथा इस मामले से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है तथा अधिसूचना में उचित स्थानों पर इन पर चर्चा की गई है।

## ड. विचाराधीन उत्पाद तथा जांच का दायरा

7. वर्तमान जांच में जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है वह रूस तथा यूरोपीय संघ(ई यू) में उत्पन्न होने वाला अथवा वहां से निर्यात किया जाने वाला विटामिन सी है। विटामिन सी को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2936.27 के तहत वर्गीकरण किया गया

है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के क्षेत्रों में किसी भी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

#### च. समान वस्तुएं

8. (क) पाटनरोधी नियमों का नियम 2(घ) यह स्पष्ट करता है कि 'समान वस्तुएं' का तात्पर्य उस वस्तु से है जो जांच के अधीन उत्पाद से हर प्रकार से सम्बन्ध या समान हो अथवा ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में कोई अन्य वस्तु जिसके लक्षण जांच के अधीन वस्तुओं से काफी मिलते जुलते हों।

(ख) याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित तथा बिक्री की गई विटामिन सी और संबद्ध देशों से आयात की गई विटामिन सी के लक्षण समान हैं और उन्हें समान वस्तुएं माना जाए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इन देशों के उत्पादकों द्वारा तथा घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई खास अंतर नहीं है, हालांकि प्रत्येक विनिर्माता अपनी उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन की प्रक्रिया में सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं। किसी अन्य पक्ष ने समान वस्तुओं के संबंध में कोई दावा नहीं किया है।

(ग) इस बात के मद्देनजर प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे विटामिन सी न्या संबद्ध देशों से आयात की जा रही विटामिन सी का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है और इस प्रकार ये दोनों वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने योग्य हैं और इसलिए ये नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं।

#### छ. घरेलू उद्योग

9. उक्त याचिका मै0 अम्बालाल साराभाई इंटरप्राईजेज लि�0 द्वारा दायर की गई है जिसका पंजीकृत कार्यालय वादी वादी, बड़ौदा-390007 में स्थित है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है। मै0 जयन्त विटामिन लि�0 नामक एक अन्य कंपनी, जिसने भारत में

विटामिन सी के विनिर्माण के लिए क्षमताओं का सृजन किया था, ने अपना प्रचालन अब बंद कर दिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता का भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है और यह घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियमों के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।

**झ. पाटन**

**सामान्य मूल्य**

11. प्राधिकारी ने धारा 9 क (1)(ग) में दिए गए नियमों के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य की जांच की है।

12. ऊपर उल्लिखित धारा की शर्तों के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी। निर्यातकों द्वारा सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के संबंध में किए गए दावे निम्नानुसार हैं-

**अ. रूस तथा यूरोपीय संघ के निर्यातक**

13. जबाब केवल मै0 बीएसएफ तथा मै0 मर्क केजीएए, जर्मनी से प्राप्त हुए थे जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यात तथा घरेलू बिक्री का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। निर्यातकों द्वारा सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के संबंध में किए गए दावों पर यहां नीचे चर्चा की जा रही है:-

ट. बी ए एस एफ, जर्मनी

**14. सामान्य मूल्य**

(i) निर्यातकों ने घरेलू बाजार में की गई विटामिन सी की बिक्री का महीना-बार और प्रस्तुत किया। मै0 बी ए एस एफ ने घरेलू बाजार में \*\*\*मिलियन अमरीकी डालर के विक्रय मूल्य की \*\*\*किंग्रा0 विटामिन सी की बिक्री की। इस प्रकार, घरेलू बाजार में की गई औसत बिक्री वसूली \*\*\*अमरीकी डालर प्रति किंग्रा0 थी। मै0 बी ए एस एफ ने विटामिन सी के लिए अपनी उत्पादन लागत भी प्रस्तुत की है। जैसा कि निर्यातक द्वारा दी गई सूचना में दर्शाया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में विटामिन सी की बिक्री घाटे पर अर्थात् अपनी उत्पादन लागत से कम मूल्य पर की है।

(ii) उपरोक्त बातों के मद्देनजर प्राधिकारी इस बात को उचित मानते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर किया जाए जिसमें प्रशासन, सामान्य खर्च एवं ब्याज, मूल्य हास तथा लाभ का एक अवयव शामिल हो। चूंकि सामान्य मूल्य उत्पादन लागत पर आधारित है इसलिए प्राधिकारी ने अन्य किसी समायोजन पर विचार नहीं किया है।

**15. निर्यात कीमत**

(i) निर्यातक ने भारत को \*\*\* अमरीकी डालर के कुल मूल्य की \*\*\* किंग्रा0 विटामिन सी का निर्यात किया है। तदनुसार जांच की अवधि के दौरान विटामिन सी की औसत निर्यात कीमत \*\*\*अमरीकी डालर प्रति किंग्रा0 बनती है। निर्यातक ने अंतर्राज्यीय माल-भाड़ा (\*\*\*विदेशी मालभाड़ा (\*\*\*)तथा पैकिंग (\*\*\*))के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने अगली जांच होने तक प्रारंभिक निष्कर्षों के उद्देश्य से इन समायोजनों की अनुमित दी है। इस प्रकार भारत को की गई निर्यात बिक्री के लिए कारखाना द्वार पर मूल्य \*\*\* डालर/किंग्रा0 बनता है।

ठ. मै0 मर्क के जी ए ए, जर्मनी

**16. सामान्य मूल्य**

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों का सौदे बार व्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है। निर्यातक ने अपनी उत्पादन लागत का व्यौरा भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी यह निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि क्या घरेलू बाजार में की गई बिक्री उत्पादन लागत से अधिक मूल्य पर की गई है और यह व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है। इसलिए प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकारी इस बात को उचित समझते हैं कि निर्यातक द्वारा दी गई सूचना की अनदेखी कर दी जाए। विस्तृत जांच होने तक प्राधिकारी यह उचित समझते हैं कि मर्क केजीएए के सामान्य मूल्य पर अन्य सहकारी उत्पाद के सामान्य मूल्य के आधार पर विचार किया जाए।

**17. निर्यात कीमत**

निर्यातक मै0 मर्क के जी एए ने भारत को \*\*\* अमरीकी डालर के कुल मूल्य की \*\*\* किग्रा0 विटामिन सी का निर्यात किया है। तदनुसार, जांच की अवधि के दौरान विटामिन सी की औसत निर्यात कीमत \*\*\* अमरीकी डालर प्रति किग्रा0 बनती है। निर्यातक ने सी आई एफ निर्यात कीमत से किसी प्रकार के समायोजनों के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्राधिकारी इस बात को उचित समझते हैं कि अन्य सहकारी निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सी आई एफ निर्यात कीमत से समायोजन किया जाए।

**18. यूरोपीय संघ के अन्य निर्यातक**

यूरोपीय संघ के अन्य निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी यह उचित मानते हैं कि इनके बारे में पाटन मार्जिन पर विचार यूरोपीय संघ के सहकारी निर्यातकों के अधिकतम पाटन मार्जिन के आधार पर किया जाए।

**19. रूस के निर्यातक**

(क) प्राधिकारी ने रूस के निर्यातकों को जांच से संबंधित सूचना प्रदान करने तथा ऊपर उल्लिखित धारा के अनुसार अपनी टिप्पणी करने, यदि कोई हो, का अवसर दिया था। प्राधिकारी ने भारत स्थित रूसी दूतावास को भी लिखा था। तथापि संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी के सूचना भेजने संबंधी अनुरोध का जबाब नहीं दिया है।

(ख) सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में याचिकाकर्ता ने जो दावा किया है उसका किसी हितबद्ध पक्ष ने खण्डन नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने नियम 6(8) के आधार पर अर्थात् उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की है।

(ग) रूस में विटामिन सी के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर जाँच शुरू करते समय ही सामान्य मूल्य का निर्धारण कर लिया गया था। प्राधिकारी ने कुछ समायोजन करने के पश्चात् सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आधार के रूप में इस पर ही विचार किया है।

(घ) निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस द्वारा संकलित सूचना के आधार पर किया गया है। औसत निर्यात कीमत का समायोजन कमीशन, बीमा, स्वदेशी भाड़ा, पैकिंग और हैंडलिंग प्रभारों के लिए किया गया है।

**20.** तुलना से संबंधित नियमावली में इस प्रकार व्यवस्था की गई:-

‘डम्पिंग मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत एवं सामान्य मूल्य में एक निष्पक्ष तुलना करेगा। यह तुलना समान स्तर के व्यापार पर की जाएगी, सामान्यतः यह कारखाना द्वार के स्तर पर एवं यथासंभव उसी अवधि में की गई बिक्री के स्तर पर होगी। कीमत की तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अन्तर के लिए प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर उचित रियायत दी जाएगी जिसमें बिक्री की शर्तों, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्रा, भौतिक विशेषताओं में अन्तर तथा अन्य ऐसे अन्तर भी शामिल हैं जिससे कीमत की तुलनीयता प्रभावित होती प्रतीत होती हो।’

**21** जैसा कि ऊपर विचार किया गया है, अलग-अलग निर्यातकों और विशिष्ट देशों के बारे में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	देश/निर्यातक	डम्पिंग मार्जिन %
1.	<u>जर्मनी</u>	
	मैसर्स बी ए एसएफ	26.19 %
	मैसर्स मर्क के जी ए ए	27.94 %
	अन्य निर्यातक	27.94 %
2.	<u>रूस</u>	
	सभी निर्यातक	38.48 %

### ठ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

22. पाटित आयात का कीमतों पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि आयातों के पाठन से कीमत में भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कोई उल्लेखनीय गिरावट आती है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक घटाने या कीमत को बढ़ने से रोकने में मदद मिली है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ सकती थी ।

23. उक्त नियमावली के परिशिष्ट II (iv) के अनुसार भारत में, घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने ऐसे साधनों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं जैसे उत्पादन क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री आय, डम्पिंग मार्जिन तथा उसका प्रभाव क्षेत्र इत्यादि ।

24. घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले विभिन्न मानदण्ड नीचे दिए गए हैं -

(क) उत्पादन

याचिकाकर्ता कम्पनी का उत्पादन वर्ष 1997-98 में हुए 303.713 मी. टन से घटकर जांच अवधि में 283.842 मी. टन रह गया था ।

(ख) बिक्री मात्रा

याचिकाकर्ता कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 1997-98 में 269.457 टन विटामिन सी की बिक्री की तुलना में वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान 234.792 टन विटामिन सी की बिक्री की थी ।

(ग) क्षमता उपयोगिता

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान 71 % क्षमता उपयोगिता प्राप्त की थी जो वार्षिक आधार पर जांच अवधि के दौरान घटकर 66 % हो गया थी ।

(घ) बिक्री वसूली

याचिकाकर्ता कम्पनी की वर्ष 1997-98 के दौरान औसत बिक्री वसूली-----रुपए/किग्रा 0 थी । जांच अवधि के दौरान बिक्री वसूली में गिरावट आई थी और यह -----रुपए/किग्रा 0 थी । तथापि, इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता कम्पनी की बिक्री वसूली अपने उत्पादन लागत से कम थी ।

(ङ.) लाभप्रदता

31 मार्च, 1998 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी को विटामिन सी के कारोबार में 530.13 लाख रुपए का घाटा हुआ था और यह घाटा वर्ष 1998-99 के दौरान बढ़कर 573.50 लाख रुपए का हो गया था ।

25. इसलिए प्राधिकारी उपरोक्त तथ्यों से यह बात नोट करते हैं कि संबंधित देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम कीमतों पर हुआ है । इसके अलावा, भारत में जो आयात हुआ है वह घरेलू उद्योग के लिए नुकसान रहित कीमतों से कम कीमतों पर हुआ है । इसके

फलस्वरूप, याचिकाकर्ता को अपने उत्पाद को अपनी उचित बिक्री कीमत से बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया था जिससे याचिकाकर्ता को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था । याचिकाकर्ता को अपनी क्षमता उपयोगिता के स्तर को बढ़ाने से भी रोका गया था । ये मानदण्ड संयुक्त एवं संचयी रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि पाटित आयातों की वजह से याचिकाकर्ता को वास्तविक क्षति पहुँची है ।

#### ड. भारतीय उद्योग का हित व अन्य मुद्दे

26. सामान्यतः पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य उस पाटन को कम करना है जो याचिकाकर्ता कंपनियों को क्षति पहुँचा रहा है और नये सिरे से भारतीय बाजार में एक खुली एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को कायम करना है जो देश के आम हित में हो ।

27. यह स्वीकार्य है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से संबद्ध सामान का उपयोग करते हुए उत्पादित वस्तुओं के मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणामतः इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है तथापि पाटन रोधी कार्रवाई द्वारा भारत में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटन रोधी शुल्क की सीमा याचिकाकर्ता कंपनियों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाये । इसके विपरीत, पाटन रोधी कार्रवाई से होने वाली पाटन के अनुचित फायदे खत्म हों, याचिकाकर्ता कंपनियों के पाटन को रोकेगी तथा विटामिन-सी के उपभोक्ता को खरीदने के लिए एक व्यापक चयन की सुविधा में मदद मिलेगी । पाटन रोधी उपाय लगाने से संबद्ध देशों से होने वाले आयातों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी । अतः इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

28. याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक पाटन विरोधी शुल्क की सीमा निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए भारत में उत्पादन क्षमता के अनुकूलतम स्तर पर उत्पादन के उचित मूल्य को ध्यान में रखकर विटामिन-सी के उचित विक्रय मूल्य पर विश्वास किया है ।

29. प्रचलित सीमाशुल्क के स्तर तथा एक प्रतिशत उत्तराई शुल्क तथा दो प्रतिशत संचालन शुल्क जोड़ने के तत्पश्चात् पाटन से संबंधित उपरोक्त पैरा में यथावर्णित रूस और ई यू से हुए विटामिन सी की निर्यात कीमत के आधार पर पहुँच कीमत का निर्धारण किया गया है।

#### ण. निष्कर्ष

30. उपर्युक्त तर्कों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं-

क. रूस और यूरोपीय संघ से निर्यातित अथवा वहाँ के मूल की विटामिन सी (एसकार्बिक एसिड) का भारत में निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर हुआ है, परिणामतः पाटन हुआ है;

ख. भारतीय उद्योग को भारी क्षति हुई है;

ग. संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण भारतीय उद्योग को संचयी रूप से नुकसान हुआ है।

31. यह आवश्यक समझा गया है कि जांच पूरी होने तक रूस और ई यू मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी के सभी आयातों पर अंतिम निर्धारण होने तक, अनंतिम रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

32. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन अथवा उससे कम राशि के बराबर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश पर विचार किया जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। इस उद्देश्य के लिए आयातों की औसत पहुँच कीमत की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कम्पनी की नुकसान रहित बिक्री कीमत से की गई थी। जहाँ अंतर डम्पिंग मार्जिन से कम था वहाँ डम्पिंग मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। यह विचार करना आवश्यक समझा गया कि जांच पूरी होने तक रूस और ई यू मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी के सभी आयातों पर अंतिम निर्धारण होने तक, अनंतिम रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

33. तदनुसार, प्राधिकारी रूस और ई यू मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी के सभी आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। सीमाशुल्क के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी के सभी

आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाया जाने वाला पाटनरोधी शुल्क की राशि नीचे दर्शाई गई सारणी की राशि होगी:-

क्र.सं.	देश/निर्यातक	राशि(प्रति किग्रा)
1.	रूस- सभी निर्यातक	85.35
2.	ई यू- मैसर्स बी ए एस एफ, जर्मनी	91.04
	ई यू- अन्य निर्यातक	150.49

34. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3 ए, 8 बी, 9 तथा 9 ए के तहत लगाए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित के अनुसार आकलन योग्य मूल्य होगा ।

त. आगे की प्रक्रिया

35. प्रारंभिक निष्कर्ष को सूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- (क) प्राधिकारी सभी इच्छुक पार्टियों से इन निष्कर्ष पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हैं और उन पर अंतिम निष्कर्ष निकालते समय विचार किया जाएगा;
- (ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता तथा अन्य इच्छुक पार्टियों को अलग से संबोधित किया जा रहा है, जो पत्र के प्रेषण की तारीख से 40 दिनों के अंदर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई दूसरी इच्छुक पार्टी भी अपने विचार इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर दे सकती हैं;
- (ग) प्राधिकारी, सभी इच्छुक पार्टियों को मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा; जो तदउपरान्त लिखित देना होगा ।
- (घ) प्राधिकारी, आवश्यक होने पर आगे फिर सत्यापन करेगा;
- (ङ) अंतिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेगा ।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2000

**Preliminary Findings**

**Subject: - Anti-Dumping investigation concerning imports of Vitamin C from Russia and European Union (EU).**

**No. 26/1/99-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

**A. PROCEDURE**

2. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:
  - i. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the Rules, received written application from M/s. Ambalal Sarabhai Enterprises, alleging dumping of Vitamin-C, originating in or exported from the Russia and European Union(EU) (hereinafter referred to as subject countries);
  - ii. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, decided to initiate investigations against imports of Vitamin-C from the subject countries. The Authority notified the Embassies/Delegations of the subject countries about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the Rules;
  - iii. The Authority issued a public notice dated 10<sup>th</sup> August, 1999 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of Vitamin-C classified under custom sub-headings 2936-2700 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975, originating in or exported from the subject countries;
  - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known exporters (whose details were made available by the petitioner) and industry associations

and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with rule 6(2);

- v. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known importers of Vitamin-C in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;
- vi. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of Vitamin-C for the past three years, including the period of investigations.
- vii. The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and the Embassies/Delegations of the subject countries in accordance with rules 6(3) supra;
- viii. The Authority sent questionnaire, to elicit relevant information, to the known exporter from Russia and European Union(EU) as indicated by the petitioner , as mentioned below in accordance with the Rule 6(4):-

### **RUSSIA**

- M/s. Belvitaminy, INC, Belgorod
- M/s. Immuno Preparations Plant
- M/s Joint Stock Company Marbiopharm
- M/s Schelkovsky Vitamin Plant
- M/s Joint Stock Company Syvtvita
- NPO Vitamins

### **European Union**

#### **UK**

- M/s. Hoffman-La-Roche, Scotland
- M/s Laporate Industries Ltd., London
- M/s Roche Products Ltd., Heanor

#### **GERMANY**

- M/s. BAYER AG
- CULTOR FOOD SCIENCE GmbH
- BASF Aktiengesellschaft
- Haffmemn Like article Roche AG
- Merck KgaA

ix. The response to the questionnaire was received from BASF Aktiengesellschaft, M/s Cultor Food Science GmbH, M/s Bayer AG and M/s Merck KgaA, Germany. None of the other exporters responded to the questionnaire.

x. The Embassies/Delegations of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporter was also sent to the Embassies/Delegations, along with a list of known exporters/producers;

xi. A questionnaire was sent to the following known importers/ wholesale dealers of Vitamin-C in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4):

- M/s. Anglo French Drugs Co. (Eastern) Ltd, Bangalore.
- M/s. American Remedies, Madras
- M/s. Bharat Laboratory Suppliers, Mumbai
- M/s. Crystal Pharmaceuticals, Calcutta
- M/s. Chemie Pharma, Mumbai
- M/s C.J.Shah & Compay, Mumbai
- M/s. Concepce Pharma Limited, Mumbai
- M/s. Dilip Kumar & Company, Mumbai
- M/s. Eros Pharma, Bangalore
- M/s. Fours (1) Labs. Pvt. Limited, Madras
- M/s. Glaxo India Ltd., Mumbai
- M/s. Gracure Pharmaceuticals Limited, New Delhi
- M/s. Khrina Pharma, Delhi
- M/s. K. Sevential & Company, Mumbai
- M/s. Lapx Chemicals Privated Ltd., Mumbai
- M/s. Lalchand Bhimraj, Mumbai
- M/s. Merit Organion Ltd., Mumbai
- M/s. Mercury Labs Limited, Mumbai
- M/s. Medley Labs, Mumbai
- M/s. Medi Pharma Drug House, Mumbai
- M/s. Nemi Pharma Private Ltd., Walkeshwar
- M/s. Puja Enterprises, Mumbai
- M/s Pardipkumar & Company, Mumbai
- M/s Pharmaceutical India, Mumbai
- M/s.Recon Limited, Bangalore
- M/s. Remidex Pharma Pvt. Ltd., Bangalore
- M/s. Stride Pharma Limited, Mumbai

- M/s. Sunways Private Ltd., Mumbai
- M/s. Taru Enterprises, Mumbai
- M/s. Turakha Brothers, Mumbai
- M/s. TH Thakore Pharma Labs., Mumbai
- M/s. Tablets India, Ltd., Chennai

The response was, however, filed by the following importers of Vitamin-C: -

- ◆ M/s K. Sevantilal & Co., Mumbai
- ◆ M/s Medi Pharma Drug House, Mumbai

- xii. Additional information regarding injury was sought from the petitioner, which was also received;
- xiii. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- xiv. The Authority conducted spot verification of the domestic industry to the extent considered necessary.
- xv. Cost investigations were also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner;
- xvi. \*\*\*\* in this notification represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xvii. Investigation was carried out for the period starting from 1<sup>st</sup> April, 1998 to 31<sup>st</sup> March, 1999.

#### **PETITIONER'S VIEWS**

3. The petitioner has expressed the following views with regard to dumping of Vitamin-C and the injury to domestic industry as a consequence thereof:
  - i) **Dumping:**
    - (a) Vitamin-C is being dumped in India by the exporters from Russia and European Union (EU). Further imports from these countries are not only substantial but also bench marks the price of the Vitamin-C in Indian market.

(b) In European Union, Vitamin-C is being imported from United Kingdom and Federal Republic of Germany. Apart from this Vitamin-C is also being imported into India from Italy, France and Denmark. These countries are members of European Union. There are also many other producers of Vitamin-C in European Union. There is no custom boundary in European Union. Thus, imposition of anti-dumping duty cannot be effective without imposing duty against European Union as a whole as other producers may start dumping of Vitamin-C in the Indian market after imposition of anti-dumping duty against United Kingdom and Germany alone. Even circumventing anti-dumping duty shall not be difficult for the producers from Germany and United Kingdom; therefore, the petitioner has requested the Designated Authority to initiate investigation against European Union cumulatively.

(c) The producers in United Kingdom and Germany have reduced their price in the Indian market. Producers from Russia were not exporting Vitamin-C earlier. The exporters from these countries started exporting Vitamin-C in Indian market recently at dumped prices.

(d) Vitamin-C is shipped in India primarily directly from Russia, United Kingdom and Germany. However, it is coming in small quantity through traders in Hong Kong and Singapore also.

(e) Market share of imports from subject countries is increasing. Share of subject countries in domestic demand was only 5.29% in 1996-97, which increased to 19.07% in 1998-99.

ii) **On injury:**

The petitioner has suffered injury as would be seen from the following:-

(a) Vitamin-C is a drug; the price of which are controlled under Drug Price (Control Order) and the price control has been in force from the year 1970 onwards.

(b) The margin of dumping from each of the subject countries is more than the limits prescribed. Quantum of imports from subject countries and other countries is available with the Designated Authority. Petitioner has claimed cumulative assessment of the effects of imports since the export price from the subject countries directly compete with the price offered by the domestic industry in the Indian market. Petitioner has requested assessment of injury to the domestic industry cumulatively from all the subject countries.

(c) Vitamin-C production of petitioner declined from 468.961 MT in 1996-97 to 287.299 MT in 1998-99.

(d) The capacity utilisation of the domestic industry has declined from 109.26% in 1996-97 to 66.84% in 1998-99. They have also submitted that should the current trend of volume of imports from these countries continue, the production of current year of the domestic industry will be much less than the production in 1998-99. As a result, the domestic industry has no option but to close their production.

(e) Sales volume of domestic industry during 1996-97 was 413.694 MT which was reduced to 234.729 MT during 1998-99, the average monthly sales volume of domestic industry which was 34.47 MT in March, 1997 declined to 19.56 MT in 1998-99.

(f) Vitamin-C average domestic realisation of petitioner during 1996-97 was Rs. \*\*\*\* per Kg. which has reduced to Rs.\*\*\*\* per Kg. during 1998-99, which shows a decline of 14%.

(g) Petitioner has also submitted that there is no significant change in the cost of production of the domestic industry for subject merchandise. Even then the domestic industry has been forced to reduce the selling prices.

(h) Due to tremendous pressure on margin, domestic industry has been forced to take a decision to reduce manpower to the extent bearable.

(i) Petitioner claimed that till 1995-96, they have been making profits. Due to dumping of Vitamin-C from subject countries, they are forced to sell Vitamin-C at below their cost of production resulting in loss of Rs.\*\*\*\* per Kg. of Vitamin-C.

(j) Due to tremendous price under cutting by the dumped imports, the domestic industry is forced to sell the subject material at prices below from the DPCO price.

**C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

**4. Views of Exporters:**

(a) The exporters M/s Caltor Food Science Gmbh, Germany and M/s Bayer AG, Germany have informed that they have not exported the subject material to India.

(b) M/s BASF Aktiengesellschaft, Germany & M/s Merck KgaA, Germany have furnished the information solicited by the Designated Authority. The

information made available by the exporters has been examined and considered by the Authority in the findings at appropriate places.

#### **5. Views of Importers:**

- (a) Claim of dumping by domestic industry only on the basis of letter from Indian High Commissioner would be misleading conclusion because the Indian High Commissioner is not competent authority to properly check prevailing domestic prices abroad..
- (b) Domestic industry is importing the intermediate 2-Keto Gulonic Acid from China PR to manufacture Vitamin-C. So it would be advisable to drop such a ridiculous anti-dumping investigation for imposing anti-dumping duty on Vitamin-C originating from major producers all over the world. Instead, the Designated Authority should recommend reduction in duty on intermediate to a level of 10%, which would be a feasible solution to make the Indian Industry survive rather than wrong protection & monopolistic situation. Even after imposing anti-dumping duty if domestic industry will not produce sufficiently, formulation Industry will suffer badly.

#### **D. EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED**

- 6. The submissions made by the exporters, importers, petitioner and other interested parties have been examined and issues raised with reference to the Rules and having a bearing on this case have been considered and dealt with at appropriate place in the notification.

#### **E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION & SCOPE OF INVESTIGATION**

- 7. The product considered in the present investigation is Vitamin-C originating in or exported from Russia and the European Union (EU). Vitamin-C is classified, under the Custom-sub heading 2936.27 of the Custom Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

#### **F. LIKE ARTICLES**

- 8. (a) Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules specifies that “Like Articles” means an article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

(b) The petitioner has claimed that the Vitamin-C produced and sold by them and those imported from the subject countries have similar characteristics and should be treated as like articles. They have also claimed that there is no significant difference in the technology adopted by petitioner and by the producers in these countries. Though, every manufacturer fine-tunes production process according to available facilities and necessities. None of the other parties have claimed any thing with regard to like articles.

(c) In view of the same, the Authority holds that Vitamin-C being produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries can be used interchangeably and thus are commercially and technically substitutable and therefore, are like articles within the meaning of the Rules.

#### **G. DOMESTIC INDUSTRY**

9. The petition has been filed by M/s. Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. having its Registered Office at Wadi Wadi, Baroda-390007. The petitioner is the sole producer of the subject goods in India. The other company M/s. Jayant Vitamin Ltd. that had created capacities from the manufacture of Vitamin-C in India has since closed its operations. Therefore, the petitioner accounts for a major proportion of the production of the subject goods in India and fulfils the requisite criteria to represent the domestic industry, as required under the Rules.

#### **H. DUMPING**

##### **Normal value:**

10. The Authority has examined Normal Value in relation to an article as per the Rules in Section 9A(1)(c).

11. The Authority sent the questionnaire to the exporters from the subject countries in terms of the section cited above. The claims made by the exporters with regards to the Normal value and the export price are as under: -

#### **I. Exporters from Russia and EU**

12. The response was received only from M/s BASF and M/s Merck KgaA , Germany who had furnished the details of the exports made to India during the period of investigation and the domestic sales. The claims made by the exporters with regard to the Normal Value and the Export Price are discussed herein under: -

J. **BASF, Germany:**

13. **Normal Value:**

- (i) The exporters furnished the month wise details of the sales of Vitamin-C in the domestic market. M/s BASF sold \*\*\*\*Kg of Vitamin-C in the domestic market at a sales value of US\$\*\*\*\*. Thus, the average sales realisation in the domestic market was US\$\*\*\*\* per kg. M/s BASF has also submitted its cost of production of Vitamin-C. It is observed from the information provided by the exporter, the company has sold Vitamin-C in domestic market at a loss i.e. below their cost of production.
- (ii) In view of the above, the Authority considers it appropriate to determine normal value on the basis of cost of production, including administrative, selling, general expenses and interest, depreciation and an element of profit. Since the normal value is based on cost of production, the Authority has not considered any other adjustments.

14. **Export Price:**

- (K) The exporter has exported \*\*\*\* Kg. of Vitamin-C to India for a total value of US\$\*\*\*\*. Accordingly, the average export price of Vitamin-C during the period of investigation works out to US\$\*\*\*\* per kg. The exporter has claimed adjustments on account of Inland Freight (\*\*), Overseas Freight (\*\*) and Packing (\*\*). Thus the Ex-factory price for export sales to India is claimed at \*\*\*\*/Kg.

L. **M/s Merck KGaA, Germany**

**Normal Value:**

- 15 The Authority notes that the exporter has not furnished information on transaction-wise details of sales made in the home market. The exporter has not furnished details of its cost of production also. The Authority cannot determine whether the sales made in the home market are above cost of production and are in the ordinary course of trade. The Authority, therefore, considers it appropriate to disregard the information furnished by the exporter for the purpose of preliminary determination. The Authority considers it appropriate to consider normal value in respect of Merck KGaA based on the normal value in respect of other co-operative exporter, pending detailed investigations.

**16. Export Price:**

The exporters M/s. Merck KGaA have exported \*\*\*\* Kg. of Vitamin-C to India for a total value of US\$\*\*\*\*. Accordingly, the average export price of Vitamin-C during the period of investigation works out to US\$\*\*\*\* per kg. The exporter has not disclosed any adjustments from the CIF export price. The Authority considers it appropriate to provide for adjustments from the CIF export price based on information made available by the other co-operating exporter.

**17. Other Exporters from EU:**

With regard to other exporters from EU, the Authority considers it appropriate to consider the dumping margin based on the highest dumping margin in respect of the co-operating exporters from EU.

**18. Exporters from Russia**

- (a) The Authority provided opportunity to the exporters from Russia to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Section cited above. The Authority also wrote to the Embassy of Russia in India. However, none of the exporters from the subject country has responded to the Authority's request for information.
- (b) The claim made by the petitioner with regard to the determination of normal value has also not been disputed by any interested party (ies). The Authority has, therefore, proceeded on the basis of Rule 6(8), i.e., best information available.
- (c) The normal value was determined at the time of initiation of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Vitamin-C in Russia as provided by the petitioner. The Authority has considered the same as the basis for determination of the Normal Value after appropriate adjustment.
- (d) The export price has been determined on the basis of the information compiled by the DGCI&S. The average export price has been adjusted for commission, insurance, inland freight, overseas freight, packing & handling charges.

**19. The Rules relating to comparison provides as follows:**

“While arriving at margin of dumping, the designated authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The

comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability.”

20. Based on the Normal Value and the Export Price, as discussed above, the dumping margins in respect of individual exporters and the specific countries, is as under: -

S. No.	Country/Exporter	Dumping Margin %
1.	<b><u>Germany</u></b> 1) M/s BASF 2) M/s Merck KGaA 3) Other Exporters	35.49% 38.77% 38.77%
2.	<b><u>Russia</u></b> All Exporters	62.56%

#### M. INJURY & CAUSAL LINK:

21. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

22. For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.

23. The various parameters indicating injury to the domestic industry are as follows: -

(a) Production: -

The production of the petitioner company has decreased from 303.713 MT in 1997-98 to 283.842 MT in the period of investigation.

(d) **Sales Quantity:** -

The petitioner company sold 234.792 tons of Vitamin-C during the financial year 1998-99 as compare to 269.457 tons in financial year 1997-98.

(e) **Capacity utilisation:** -

The company achieved capacity utilisation of 71% during the financial year 1997-98, which decreased to 66% during the period of investigation on an annualised basis.

(d) **Sales Realisation:** -

The average sales realisation of the petitioner company during 1997-98 was Rs.\*\*\*\*\*/Kg. There was a decline in the sales realisation during the period of investigation and the same was at Rs.\*\*\*\*\*/Kg.. However, the sales realisation of the Petitioner Company during the period was below its cost of production.

(e) **Profitability:**

During the financial year ending 31<sup>st</sup> March, 1998, the losses of the company from the Vitamin-C operation was Rs.530.13 lacs. The losses further increased to Rs.573.50 lacs during the year 1998-99.

24. The Authority, therefore, notes from the above that the imports from the subject countries have been at a price below the selling prices of the domestic industry. Further, the imports into India have been at a price lower than the non-injurious price for the domestic industry. As a consequence thereof the petitioner was forced to sell its product at a price significantly below its reasonable selling price resulting in financial losses to the petitioner. The petitioner was also prevented from increasing the level of capacity utilisation. These parameters collectively and cumulatively indicate that the petitioner has suffered material injury due to the dumped imports.

N. **INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

25. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the petitioner companies and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

26. It is recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty

is restricted to an amount necessary to redress the injury to the petitioner companies. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the petitioner companies and help maintain availability of wider choice to the consumers of Vitamin-C. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

27. To ascertain the extent of anti-dumping duty necessary to remove the injury to the petitioner companies, the Authority has relied upon non - injurious selling price of Vitamin-C in India for the petitioner companies, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation for the petitioner companies.

**O. LANDED VALUE:**

28. The landed value has been determined on the basis of export price of Vitamin-C from Russia and EU, as detailed above in the para relating to dumping, after adding the prevailing level of customs duties and one percent towards landing and two percent towards handling charges.

**P. CONCLUSIONS:**

29. After considering the foregoing the Authority concludes that:

- (a) Vitamin-C(Ascorbic Acid) originating in or exported from Russia and European Union(EU) has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- (b) The Indian industry has suffered material injury ;
- (c) The injury has been caused cumulatively by the imports from the subject countries.

30. It is considered necessary to impose anti dumping duty, provisionally, pending final determination, on all imports of Vitamin-C originating in or exported from Russia and EU pending investigations.

31. The authority considered recommending the amount of Anti-Dumping Duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to domestic industry. The average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the non-injurious selling price of the Petitioner Company, determined for the period of investigations. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. It is considered necessary to impose antidumping duty, provisionally, pending final determination on all imports of Vitamin-C originating in or exported from Russia and EU pending further investigation.

32. Accordingly, the Authority recommends that provisional duties be imposed, on all imports of Vitamin-C originating in or exported from Russia and EU. The Anti-Dumping duty shall be the amounts indicated in the table below, to

be imposed from the date of Notification to be issued in this regard by the Central Govt. on all the imports of Vitamin-C falling under Chapter 29 of the Customs Tariff, originating in or exported from the countries mentioned below:-

S. No.	Exporter/Country	Amount (Rs. per kg)
1.	Russia- All Exporters	150.49
2.	EU- M/s. BASF, Germany	85.35
	EU-Other exporters	91.04

33. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Q. **FURTHER PROCEDURE:**

34. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the dispatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.
- (c) The Authority would provide opportunity to all the interested parties for oral submissions to be rendered thereafter in writing.
- (d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- (e) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority